दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, शुक्रवार 28 मई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 237

महत्वपूर्ण एवं खास

केंद्र ने राज्यों को दिए 22 करोड़ से अधिक टीके

❐ अगले तीन दिन में पहुंचेगी 11 लाख वैक्सीन

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 22 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन के डोज उपलब्ध कराये हैं। जबकि राज्यों के पास अभी 1.84 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं। इसके अलावा 11 लाख वैक्सीन राज्यों को अगले तीन दिन में मिल जायेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन मुफ्त और सीधे खरीद की कैटेगरी में उपलब्ध कराया गया है। भारत में इस समय कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत सरकार से अपने कोविड-19 रोधी टीके के लिए मंजूरी मांगते हुए कहा है कि इसकी वैक्सीन 12 साल और इससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षित और बेहद प्रभावी है।

जमानत देते हुए कोर्ट अपराध की गंभीरता को देखें : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत को एक आरोपी को जमानत देने से पहले कथित अपराध की गंभीरता का मूल्यांकन करना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए यह टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में अपराध की गंभीरता से इतना बेखबर नहीं हो सकता, जिसमें शादी के साल भर के अंदर की एक महिला का अस्वाभाविक अंत हो जाए। पीठ ने कहा कि कथित अपराध की गंभीरता का मूल्यांकन उन आरोपों की पृष्ठभूमि में भी होना चाहिए, जिसमें महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। साथ ही उसकी मौत के समय आरोपियों द्वारा की गई टेलीफोन कॉल की भी जांच होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना के विशिष्ट आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अकारण कोई आदेश न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के खिलाफ है। पीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत याचिका पर फैसला सुनाते हुए जज को विवेकपूर्ण तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए।

फर्जी कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बन ठगी करने वाले दो लोग गिरफ्तार

लखनऊ (आरएनएस)। पीजीआई कोतवाली पुलिस ने बीती देर रात चेकिंग के दौरान दिल्ली नंबर की नीली बत्ती लगी और भारत सरकार लिखी गाड़ी को संदिग्ध मान कर रोक लिया, उसमें बैठे लोगों ने अपने को वाणिज्य कर अधिकारी बताते हुए पुलिस को अर्दब में लेने की कोशिश की,पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंस्पेक्टर पीजीआई आनंद प्रकाश शुक्ल ने बताया कि, पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम रितेश उपाध्याय, और अखण्ड प्रताप सिंह,बताया है, अपने को कभी वाणिज्य कर अधिकारी, और कभी इनकम टैक्स विभाग का असिस्टेंट कमिश्नर बताते हैं। दोनो आरोपी नीली बत्ती लगी मारुति डिजायर से कोरोना की उपयोगी दवाइया और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हैं। जांच में पता चला है कि दो दिन पहले इनके गिरोह के कुछ साथियों को गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कई इंजेक्शन बरामद किए थे।

छत्तीसगढ़ के क़रीब दस हज़ार गाँव हुए कोरोना से मुक्त, राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत तक बनाया नेटवर्क

नई दिल्ली (आरएनएस)। देशभर में गांवों तक पहुंच रहे कोरोना-संक्रमण के अंदेशों के बीच अच्छी खबर यह है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के आधे करीब 10 हजार गांव पूरी तरह संक्रमण मुक्त हैं। इन गांवों तक या तो संक्रमण नही पहुंच पाया है, या फिर उन्हें संक्रमण से जल्द मुक्ति मिल चुकी है। यह सब समय रहते छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गांवों तक संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरु किए गए उपायों की वजह से यह संभव हो पाया है।

छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत होते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निर्देश दिए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की रोकथाम के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं। इस निर्देश के बाद पहली लहर के दौरान गांवों में स्थापित क्वारंटाइन सेंटरों को पहले से अधिक मजबूत व्यवस्थाओं के साथ फिर से सक्रिय किया गया। अन्य राज्यों अथवा शहरी क्षेत्रों से गांव लौटने वाले व्यक्तियों तथा परिवारों को इन सेंटरों में ठहराने, उनकी जांच तथा उपचार की व्यवस्था की गई। घर-घर तक सर्वेक्षण कर संक्रमितों का पता लगाने के लिए मितानिनों, तथा स्वास्थ्य अमले के साथ-साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को भी सक्रिय किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों ने सर्दी-बुखार के मरीजों की पहचान करने के साथ-साथ उनके उपचार में भी अपनी भागीदारी निभाई। कोरोना से बचाव एवं उपचार के प्रति जागरुकता लाने में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर समय रहते गांव-गांव तक आवश्यक दवाइयों के किट की आपूर्ति और उसका वितरण सुनिश्चित किया गया। जिला पंचायतों से लेकर ग्राम पंचायत तक के नेटवर्क के जरिये कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे उपायों की मानिटरिंग का काम स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। वे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन-प्रतिनिधियों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं, साथ ही फीडबैक के आधार पर अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे ह। राज्य में टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाने के लिए लगातार नये लैबों की स्थापना की गई। इससे सेंपलों की रोज होने वाली टेस्टिंग की संख्या 21-22 हजार से बढ़कर अब प्रतिदिन 70 हजार से अधिक हो चुकी है। जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं को मजबूत किया गया। अस्पतालों में पूर्व से उपलब्ध बिस्तरों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ-साथ नये कोविड सेंटरों की स्थापना कर उपचार सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। ग्रामीण क्षेत्र के गंभीर मरीजों को जल्दी से जल्दी अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके इसके लिए एंबुलेंस तथा अन्य वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी की गई।

राज्य शासन द्वारा माइक्रो लेबल तक की गई चाक-चैबंद व्यवस्थाओं के कारण छत्तीसगढ़ के कुल 20 हजार 092 गांवों में से करीब आधे 9 हजार 462 गांव आज कोरोना के संक्रमण से मुक्त हैं। इसमें बालोद जिले के 704 में से 183 गांव, बलौदाबाजार जिले के 957 में से 402, बलरामपुर के 636 में से 102, बस्तर जिले के 589 में से 252, बेमेतरा जिले के 702 में से 311, बीजापुर जिले के 579 में से 491, बिलासपुर जिले के 708 में से 96, दंतेवाड़ा के 229 में से 158, धमतरी के 633 में से 176, दुर्ग के 385 में से 377, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के 222 में से 39, गरियाबंद के 722 में से 342 गांव संक्रमण मुक्त हैं। इसी तरह जांजगीर-चांपा जिले के 887 में से 150 गांव, जशपुर के 766 में से 319, कांकेर के 1084 में से 792, कबीरधाम के 1035 में से 832, कोंडागांव के 569 में से 407, कोरबा के 716 में से 280, कोरिया के 638 में से 352, महासमुंद के 1153 में से 532, मुंगली में 711 में से 338, नारायणपुर में 422 में से 362, रायगढ़ में 1435 में से 173, रायपुर में 478 में से 261, राजनांदगांव में 1599 में से 1204, सुकमा में 406 में से 194, सुरजपुर में 544 में से 140 और सरगुजा जिले में 583 गांव में से 197 गांव संक्रमण मुक्त हैं।

भारत में ट्रायल बिना विदेशी वैक्सीन को मिलेगी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में टीकाकरण को तेजी देने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विदेशों में निर्मित अच्छी तरह से स्थापित कोविड-19 रोधी टीकों के लिए भारत में ट्रायल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। सरकार के इस कदम से विदेशी टीकों के आयात में तेजी आएगी।

केंद्र सरकार ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब देश में दूसरी लहर कुछ शांत पड़ने के बावजूद प्रतिदिन करीब 2 लाख नए संक्रमित मिल रहे हैं और हजारों लोगों की मौत हो रही है। भारत में इस समय एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित और भारत में उत्पादित कोविशील्ड और भारत बायोटेक-आईसीएमआर के टीके कोवैक्सीन से लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। रूसी वैक्सीन स्पूतनिक वी को भी सरकार आपातकालीन मंजूरी दे चुकी है, लेकिन अभी इसके कुछ लाख टीके ही रूस से लाए गए हैं और आने वाले दिनों में भारत में भी उत्पादन किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि जल्दी से जल्दी टीकों के आयात के लिए फाइजर से बातचीत चल रही है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन और मोडर्ना के साथ भी चर्चा हुई है। पिछले महीने भारत सरकार ने विदेशी टीकों को फास्ट-ट्रैक मंजूरी देने का वादा किया था, लेकिन स्थानीय ट्रायल पर जोर देने की वजह से फाइजर से बातचीत अटकी हुई थी। सरकार ने एक बयान में कहा, दूसरे देशों में उत्पादित अच्छे टीकों के लिए स्थानीय ट्रायल की अनिवार्यता में छूट के लिए प्रावधानों को बदला गया है।

कोरोना संक्रमण में उतार चढ़ाव जारी, मौतों से खौफ

» एक दिन में 2,11,298 नए मामले, 3,847 लोगों की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में पिछले एक दिन कोरोना के 2,11,298 नए मामले सामने आये, जबकि 3,847 लोगों की मौत की मौत हो गई। देश में कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन कोरोना के कारण हो रही लगातर मौत चिंता का कारण बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के कारण 3,847 लोगों की मौत की मौत हुई। इनके साथ देश में अब तक संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,15,235 हो गई है। वहीं इस दौरान संक्रमण के 2,11,298 नए मामले आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,73,69,093 हो गई।

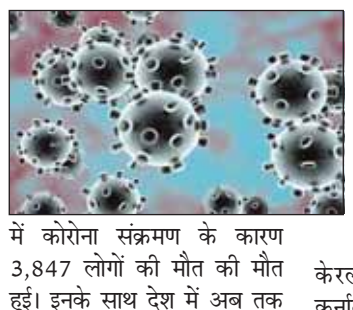

देश में अभी 24,19,907 सक्रीय मरीजों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो 8.84 फीसदी हैं। तमिलनाडु और केरल ने सभी राज्यों में सबसे अधिक नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। इसके बाद केरल में 28,798 मामले, कर्नाटक में 26,811 मामले, महाराष्ट्र में 24,752 मामले और आंध्र प्रदेश में 18,285 मामले हैं।

पिछले एक दिन में आए कुल 2,11,298 ताजा कोविड मामलों में से इन पांच राज्यों से 62.66त्न मामले सामने आए हैं, जिनमें अकेले तमिलनाडु 15.98त्न ताजा मामलों के लिए जिम्मेदार है। कुल 2,11,298 ताजा कोविड मामलों में से, इन पांच राज्यों से 62.66त्न मामले सामने आए हैं, जिनमें अकेले तमिलनाडु 15.98त्न ताजा मामलों के लिए जिम्मेदार है। वहीं भारत में भी पिछले 24 घंटों में 3,847 मौतें दर्ज की गईं। 992 मौतों के साथ महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोविड हताहत हुए हैं, इसके बाद कर्नाटक में 530 मौतें हुई हैं। इस बीच भारत ने पिछले 24 घंटों में कुल 18,85,805 वैक्सीन खुराकें दी हैं, जो कुल 20,26,95,874 हैं।

प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान 'यास' के व्यापक प्रभावों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान 'यास' के व्यापक प्रभावों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों के विभिन्न पहलुओं, तूफान से हुए नुकसान के आकलन और संबंधित विषयों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

इस दौरान यह चर्चा की गई कि एनडीआरएफ की लगभग 106 टीमों को तैनात किया गया था। पश्चिम बंगाल/ओडिशा में से प्रत्येक में तैनात की गई 46 टीमों ने 1000 से भी अधिक व्यक्तियों की जान बचाई और 2500 से भी अधिक पेड़ों/खंभों को हटाया जो सड़कों पर गिर गए थे और जिनकी वजह से वहां आवागमन बाधित हो गया था। रक्षा बलों यथा थल सेना और तटरक्षक बल ने तूफान में विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए लोगों की भी जान बचाई, जबकि नौसेना और वायु सेना अलर्ट पर थीं।

वैसे तो संबंधित राज्य चक्रवाती तूफान यास की वजह से हुए नुकसान के आकलन में अभी जुटे हुए हैं, लेकिन उपलब्ध प्रारंभिक रिपोर्टों से यही पता चलता है कि सटीक पूर्वानुमान लगाने और तूफान प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से प्रभावकारी ढंग से संवाद करने के साथ-साथ राज्यों एवं केंद्रीय एजेंसियों द्वारा समय पर लोगों की सुरक्षित निकासी करने से जान-माल का कम-से-कम नुकसान सुनिश्चित हो पाया। इसके साथ ही सैलाब या अतिवृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है। तूफान से प्रभावित अधिकतर क्षेत्रों में बिजली और दूरसंचार सेवाएं बहाल कर दी गई हैं।

प्रधानमंत्री ने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में केंद्र और राज्यों की एजेंसियों द्वारा निभाई गई अत्यंत प्रभावकारी एवं सक्रिय भूमिका को रेखांकित किया और इसके साथ ही विभिन्न एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि तूफान प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जीवन जल्द से जल्द बहाल हो और इसके साथ ही तूफान से प्रभावित व्यक्तियों के बीच राहत का वितरण उचित रूप से हो जाए।

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विद्युत सचिव, दूरसंचार सचिव एवं आईएमडी के डीजी और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।

भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के लिए जीएमपी के मुद्दों पर ब्राजीली नियामक को नया आवेदन भेजा

हैदराबाद (आरएनएस)। भारत बायोटेक ने ब्राजील में कोविड-19 रोधी टीके की आपूर्ति करने के लिए प्रमाण पत्र हासिल करने की खातिर वहां अधिकारियों को एक नया अनुरोध भेजा है। इससे पहले ब्राजील के स्वास्थ्य नियामक ने कंपनी के संयंत्र में 'वस्तु उत्पादन प्रणाली' से असंतुष्ट होने पर कोविड टीकों की आपूर्ति की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। ब्राजील की राष्ट्रीय स्वास्थ्य निगरानी एजेंसी 'एनविसा' के मुताबिक भारत बायोटेक ने 25 मई को अनुरोध भेजा था। इससे एक दिन पहले वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोवैक्सीन की दो करोड़ खुराक के आयात की मंजूरी पाने की खातिर नया आवेदन दिया था। इससे पहले एनविसा के अधिकारियों ने पाया था कि जिस संयंत्र में टीके का उत्पादन किया जाता है, वह 'वस्तु उत्पादन प्रणाली (जीएमपी)' की आवश्यकताओं पर खरा नहीं उतरता है जिसके बाद एजेंसी ने कोवैक्सीन आयात करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने 26 फरवरी को कहा था कि कोवैक्सीन की दो करोड़ खुराकों की आपूर्ति के लिए उसने ब्राजील की सरकार के साथ एक समझौता किया है। उसने बताया था कि ये खुराकें वर्तमान वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही में भेजी जाएंगी।

देश में कोरोना से रिकवरी दर 90 फीसदी हुई

» टीके अलग-अलग डोज की ली हैं तो घबराने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर अहम जानकारी दी है। मंत्रालय ने प्रेस वार्ता में कहा कि 24 राज्यों ने पिछले सप्ताह से सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले उन्होंने कहा कि 3 हफ्ते पहले 531 जिलों में रोज 100 नए मामले प्रतिदिन दर्ज किए जाते थे, अब ऐसे जिले 359 रह गए

हैं। देश में आज 2,83,000 रिकवरी दर्ज की गई हैं। 23 राज्य देश में ऐसे हैं, जहां प्रतिदिन रिकवर मामलों की संख्या नए मामलों से ज्यादा है। रिकवरी रेट अब 90 फीसदी हो गई है। जबकि पॉजिटिविटी रेट देश में 10.45 फीसदी रह गई है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक 45 साल से अधिक आयु के 14.85 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। 18-44 साल के बीच के लोगों को अब तक 1.39 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं।

❐ टीके की दूसरी डोज देने पर सतर्क रहने की जरूरत

मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप में कमी आ रही है, हमारा मानना है कि पाबंदियों में सार्थक ढील देने पर भी यह परिपाटी बनी रहेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि अगर कोविड-टीके की दूसरी खुराक में अलग टीका दिया जाता है तो उसके उल्लेखनीय दुष्प्रभाव होने की आशंका नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।

सीमा शुल्क के बगैर ब्लैक फंगस की दवा के आयात की अनुमति

नई दिल्ली (आरएनएस)। ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन आयात करने पर सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस दवा की भारी कमी को देखते हुए आज सीमा शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है।

जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने कहा है कि इस दवा पर सीमा शुल्क में केंद्र सरकार द्वारा छूट देने के लिए अंतिम फैसला लिए जाने तक आयातकों द्वारा अनुबंध पत्र के आधार पर सीमा शुल्क का भुगतान किए बगैर दवा का आयात कर सकते हैं। बेंच ने कहा कि

ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से पीड़ित हजारों लोगों की जान बचाने के लिए इस दवा की तत्काल जरूरत है। बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार को जब तक इस दवा की कमी है, तब तक के लिए इस पर सीमा शुल्क में छूट देने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि एम्फोटेरिसिन बी का किसी भी व्यक्ति को असल सीमा शुल्क का भुगतान किए बगैर ही आयातक द्वारा अनुबंध पत्र पेश किए जाने पर उस समय तक दवा आयात करने की अनुमति दी जाए, जब तक सरकार इस पर फैसला नहीं ले लेती है।

बेंच ने आदेश में कहा है कि आयातक को इसमें इस बात का हलफनामा देना होगा कि यदि सरकार द्वारा आयात शुल्क में छूट नहीं दी जाती, तो इस शुल्क का भुगतान आयातकर्ता करेगा। यह मामला ब्लैक फंगस के एक मरीज द्वारा दायर याचिका पर बहस के दौरान उठा जिसे दवा नहीं मिल रही थी। एक वकील ने अदालत को सूचित किया कि दवा पर आयात शुल्क 27 प्रतिशत है जबकि अन्य वकील ने कहा कि यह 78 प्रतिशत है।

केंद्र के वकील ने कहा कि उन्हें ठीक-ठीक प्रतिशत के बारे में नहीं पता और सक्षम प्राधिकरण से निर्देश प्राप्त करने के बाद वह अदालत को सूचित करेंगे। केंद्र सरकार के स्थायी वकील कीर्तिमान सिंह ने दलील दी कि ऐसी दवाओं पर आयात शुल्क में छूट देने के मुद्दे की जानकारी आज अधिकारियों को दे दी जाएगी और जल्द ही फैसला लिया जाएगा। बेंच ने कहा कि उम्मीद है कि केंद्र आयात शुल्क में छूट देने पर विचार करेगा। बेंच ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह दवा देश में हजारों लोगों को संक्रमित कर रहे ब्लैक फंगस से संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए जरूरी है, केंद्र सरकार इन दवाओं पर सीमा शुल्क में पूर्ण रूप से छूट देने पर गंभीरता से विचार करे कम से कम तब तक भारत में इसकी आपूर्ति कम है। अदालत को केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया कि सीमा शुल्क विभाग ब्लैक फंगस और कोविड-19 से संबंधित सभी खेपों को बिना किसी देरी के मंजूरी देगा।